BRDU International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN :2455-278X
(A peer reviewed and refereed Journal)
Vol.9, Issue.I, January 2024, Pc:BRDU-2401002

उच्च शिक्षा तक पहुंच में लैंगिक असमानताः झारखंड के रांची जिले का एक केस स्टडी

Reeta kumari, Research scholar
Department of Sociology, Radha Govind University
Ramgarh, Jharkhand

Dr. Mamta Maurya, Assistant Professor
Department of Sociology, Radha Govind University
Ramgarh, Jharkhand

अमूर्त

इस अध्ययन में झारखंड राज्य के रांची जिले में उच्च शिक्षा में लिंग भेदों की जांच के लिए तीन सौ व्यक्तियों के एक नमूने का उपयोग किया गया है। इस अनुसंधान का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि पुरुष और महिला छात्रों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाधाएँ और अवसर क्या हैं। शैक्षिक अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करने वाले सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, और संस्थागत तत्वों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नावली पर आधारित एक तकनीक का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से पता चलता है कि एक बड़ा लिंग अंतर है, जिसमें महिला छात्रों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि वित्तीय प्रतिबंधों, सामाजिक दायित्वों और लिंग के बारे में गहरे समावेशित पूर्वाग्रहों के कारण है। सांस्कृतिक मानदंड आमतौर पर पुरुष शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देते हैं, जबकि अपर्याप्त वित्तीय साधन और संस्थागत समर्थन महिला भागीदारी के लिए और भी बाधाएँ प्रस्तुत करते हैं। यह अनुसंधान इस बात पर जोर देता है कि इस अंतर को समाप्त करने और सभी को शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नीति उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।

कीवर्डः लैंगिक असमानता, उच्च शिक्षा, रांची जिला, झारखंड, शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक–आर्थिक कारक, सांस्कृतिक बाधाएं, लैंगिक रूढ़िवादिता

परिचय

शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, किसी भी समाज में सामाजिक–आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक तत्वों में से एक है। यह न केवल व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, और समग्र मानव विकास में भी योगदान करता है। हालांकि, समान शिक्षा के लिए विभिन्न प्रयासों और पहलों के बावजूद, विशेष रूप से ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लिंग भेद बने हुए हैं। भारत में, झारखंड के रांची जिले जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में पुरुष और महिला छात्रों के बीच स्पष्ट असमानताएँ देखी जाती हैं।

शिक्षा, अपनी मौलिकता में, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण मानी जाती है, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा बेहतर नौकरी के अवसरों, सामाजिक स्थिति में सुधार, और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी के लिए दरवाजे खोलती है। फिर भी, लिंग एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है जो यह निर्धारित करता है कि ऐसे अवसरों तक किसका पहुंच है। रांची जैसे क्षेत्रों में, जहां सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ गहरे अंतर्निहित सांस्कृतिक मानदंडों और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, महिला छात्रों को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएँ वित्तीय प्रतिबंधों, विवाह और घरेलू जिम्मेदारियों के संबंध में सामाजिक अपेक्षाओं से लेकर, शैक्षणिक संस्थानों में अपर्याप्त सुविधाओं और महिला–मैत्रीपूर्ण वातावरण की कमी जैसे संस्थागत सीमाओं तक फैली हुई हैं।

यह अध्ययन रांची जिले में उच्च शिक्षा तक पहुंच में लिंग भेदों की सीमा की जांच करके इन जटिलताओं में गहराई से उतरने का प्रयास करता है। पुरुष और महिला दोनों छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके, यह अध्ययन इन भेदों के मूल कारणों और उन विशिष्ट चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है जो असमान रूप से महिला छात्रों को प्रभावित करती हैं। 300 उत्तरदाताओं के विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से, यह शोध उन सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, और संस्थागत कारकों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है जो उच्च शिक्षा तक पहुंच को बाधित या सुगम बनाते हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य न केवल भेदों को मापना है, बल्कि इस क्षेत्र में महिला छात्रों के जीने के अनुभवों के बारे में गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना भी है। वे जिन विशेष बाधाओं का सामना करती हैं, उन्हें समझने से अधिक प्रभावी और लक्षित नीति हस्तक्षेपों के विकास में सहायता मिलेगी। ये हस्तक्षेप शिक्षा में लिंग भेद को पाटने में मदद कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यक्तियों, लिंग की परवाह किए बिना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने समुदायों के समग्र विकास में योगदान करने के लिए समान अवसर प्राप्त हों।

साहित्य की समीक्षा

सिंह, ए. (2020) भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 यह कहता है कि ष्राज्य किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा।ष लेकिन जब बात भारत में महिलाओं की होती है, तो यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि वे हमेशा भेदभाव का सामना करती आई हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय समाज में उत्पन्न लिंग अंतर महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए लिंग भेदभाव के कारण है। साक्षरता और शिक्षा में लिंग अंतर लिंग असमानता का एक महत्वपूर्ण आयाम है, और यह सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के स्तर को और बढ़ा दिया जाता है और जब एक प्रकार का भेदभाव (विशेष रूप से इस मामले में लिंग) अन्य प्रकार के भेदभाव के साथ मिल जाता है, जैसे जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर, तो वे और भी कमजोर हो जाती हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में कुल जनसंख्या का 26ः आदिवासी हैं (भारत के जनगणना कार्यालय)। अधिकांश आदिवासियों का व्यवसाय कृषि है, जिसकी उत्पादकता सामान्यतरू कम होती है, इसलिए अधिकांश आदिवासी लड़कियाँ परिवार के व्यवसाय में भाग लेकर और घरेलू काम करके परिवार की आय में योगदान करती हैं। चूंकि उनमें से एक उच्च संख्या जीविका संबंधी कार्यों में संलग्न होती है, इसलिए उनमें से कई स्कूल में दाखिला लेने से रोक दी जाती हैं। 2015–16 में किए गए झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर लड़कियों के छात्रों का नामांकन 50ः पाया गया। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता 77.5 प्रतिशत थी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 55.2 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, झारखंड में स्कूल के बच्चों के लिए ड्रॉपआउट दर भारत में सबसे अधिक है (100 में से केवल 30 बच्चे स्कूल पूरा करते हैं)। आदिवासियों के बीच ड्रॉपआउट दर सभी समुदायों में सबसे अधिक है। इसके विपरीत, झारखंड ने 2011 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अपनाया, जिसमें संसद द्वारा पारित अधिनियम के मूल संस्करण से निकाले गए अपने नियमों और विनियमों का निर्धारण किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि, ''राज्य इस संविधान की प्रारंभिक तिथि से दस वर्षों के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।'' इसलिए, शोधकर्ता उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए झारखंड में लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर शोध करना चाहते हैं।

नायक, के. वी., – आलम, एस. (2022) कोविड–19 महामारी के शिक्षा पर संभावित परिणामों का विश्लेषण करते समय, यह स्पष्ट है कि इसने वैश्विक स्तर पर मौजूदा शैक्षिक असमानताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला। हालाँकि, यह कम ज्ञात है कि डिजिटल विभाजन ने पारंपरिक शैक्षणिक प्रणाली को कैसे बिगाड़ा और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों के बीच पूर्व–निर्धारित लिंग असमानताओं को मजबूत किया। यह शोध पत्र इस बात की खोज करता है कि कैसे महामारी के साथ–साथ डिजिटल विभाजन ने सामाजिक रूप से वंचित समूहों (जैसे आदिवासी, जिन्हें स्वदेशी या आदिवासी भी कहा जाता है) के बीच शैक्षिक प्रणाली को खराब कर दिया और उन्हें असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया। यह पत्र इस पर विचार करता है कि कोविड–19 महामारी ने शैक्षिक असमानताओं की पूर्व–निर्धारित समस्याओं को कैसे पुनः–गठित किया और डिजिटल विभाजन ने विशेष रूप से युवा आदिवासी लड़कियों को कैसे प्रभावित किया। इस अध्ययन के लिए झारखंड, भारत के एक दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी छात्रों, उनके माता–पिता और शिक्षकों के साथ अर्ध–संरचित साक्षात्कार किए गए ताकि ऑनलाइन शिक्षा मोड में परिवर्तन के अनुभवों को समझा जा सके। पहुँच और बुनियादी ढांचे की समस्या के अलावा, निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों के तत्व (लड़कियों के लिए शिक्षा के संभावित लाभों से संबंधित और माता–पिता तथा शिक्षकों के डिजिटल शिक्षा वितरण के प्रभावशीलता के प्रति विश्वास या मान्यताएँ) आदिवासी लड़कियों के लिए डिजिटल विभाजन का निर्माण और उसे मजबूत करते हैं। साक्षात्कार से एकत्रित जानकारी के आधार पर, अध्ययन डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर पुनर्विचार करने और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बीच बिगड़ते डिजिटल विभाजन और शैक्षिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने पर जोर देता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- रांची जिले में उच्च शिक्षा में लिंग विषमताओं के स्तर का अध्ययन करना।
- पुरुष और महिला छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँचने पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों की पहचान करना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिला छात्रों को सामना करने वाली संस्थागत बाधाओं का अन्वेषण करना।

- उच्च शिक्षा में लिंग के अंतर को समाप्त करने के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना।

शोध कार्यविधि

1. शोध डिजाइन

यह अध्ययन एक मात्रात्मक शोध डिजाइन को अपनाता है, जो झारखंड के रांची जिले में 300 उत्तरदाताओं से प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण विधि का उपयोग करता है। अध्ययन में उच्च शिक्षा में लिंग विषमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और विभिन्न सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, और संस्थागत बाधाओं का अन्वेषण किया गया है जो पुरुष और महिला छात्रों पर अलग–अलग प्रभाव डालती हैं।

2. नमूना आकार और चयन

इस अध्ययन के लिए नमूना आकार 300 उत्तरदाताओं का है, जिसमें 18द्25 वर्ष की आयु के दोनों पुरुष और महिला छात्र शामिल हैं, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा में नामांकित हैं या जिन्होंने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है। उत्तरदाताओं का चयन रांची जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से स्तरित यादृच्छिक नमूना तकनीक का उपयोग करके किया गया है ताकि विविध सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों से एक प्रतिनिधि नमूना सुनिश्चित किया जा सके।

- *उत्तरदाताओं की संख्या* –300
- *लक्ष्य समूह*– पुरुष और महिला छात्र (18–25 वर्ष)
- *स्थान*– रांची जिला, झारखंड

3. शोध उपकरण

इस अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके एकत्र किया गया। प्रश्नावली को उच्च शिक्षा तक पहुँचने में लिंग विषमताओं के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, और संस्थागत कारकों पर केंद्रित है। प्रश्नावली में बंद और खुले प्रश्न दोनों शामिल थे और इसे निम्नलिखित अनुभागों में विभाजित किया गयारू

1. जनसांख्यिकीय जानकारी– आयु, लिंग, परिवार की आय, माता–पिता की शिक्षा स्तर।
2. सामाजिक–आर्थिक बाधाएँ– वित्तीय प्रतिबंध, घरेलू जिम्मेदारियाँ, शैक्षणिक संस्थानों की दूरी।
3. सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ– लिंग पूर्वाग्रह, सामाजिक अपेक्षाएँ, माता–पिता का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।
4. संस्थानिक बाधाएँ– छात्रवृत्तियों की उपलब्धता, लिंग–संवेदनशील बुनियादी ढाँचा, फैकल्टी समर्थन।
5. उच्च शिक्षा की धारणा– उच्च शिक्षा के महत्व के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण।

अधिकांश प्रश्नों के लिए उत्तरदाताओं की विभिन्न बाधाओं पर राय को आकलन करने के लिए लिकर्ट स्केल (1–5) का उपयोग किया गया। व्यक्तिगत अनुभवों पर गुणवत्ता संबंधी अंतर्दृष्टियाँ एकत्र करने के लिए खुले प्रश्न शामिल किए गए।

4. डेटा संग्रह

डेटा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों के माध्यम से उत्तरदाताओं से एकत्र किया गया। प्रश्नावली शैक्षणिक संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की गई, और ऑनलाइन सर्वेक्षण उन लोगों को वितरित किए गए जिनके पास इंटरनेट की पहुँच थी। सर्वेक्षण एक अवधि (अगस्त–सितंबर 2024) में किया गया।

5. डेटा विश्लेषण

एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण वर्णात्मक और व्युत्पन्न सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके किया गया। जनसांख्यिकीय डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने और मुख्य रुझानों को उजागर करने के लिए औसत, मध्य और मोड जैसे वर्णात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया। लिंग और शिक्षा तक पहुँच, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, और सांस्कृतिक बाधाओं के बीच संबंधों का अन्वेषण करने के लिए व्युत्पन्न सांख्यिकी, जिसमें ची–स्क्वायर परीक्षण और टी–टेस्ट शामिल हैं, का उपयोग किया गया।

परिणाम और चर्चा

तालिका 1 उत्तरदाताओं का लिंग

लिंग	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	150	50.0%
महिला	150	50.0%

कुल	**300**	**100.0%**

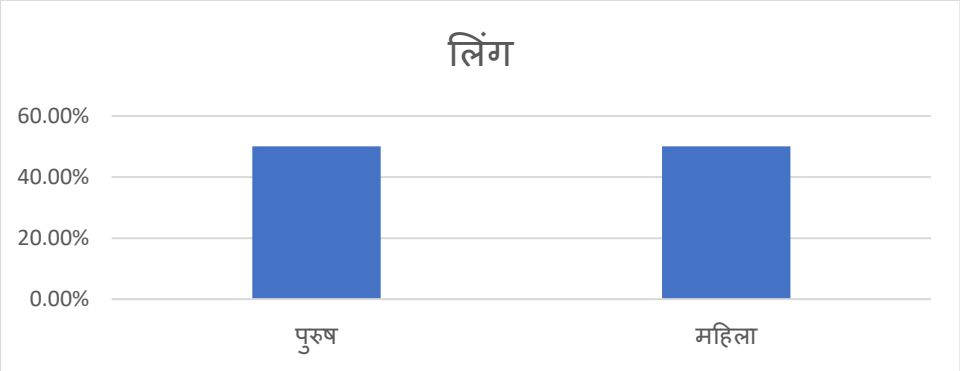

आकृति 1 उत्तरदाताओं का लिंग

यह तालिका अध्ययन में उत्तरदाताओं के लिंग वितरण को दर्शाती है, जिसमें पुरुष और महिला प्रतिभागियों का समान प्रतिनिधित्व है, प्रत्येक समूह कुल 300 नमूना आकार का 50: है। यह संतुलित प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा में लिंग विषमताओं का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों लिंगों से दृष्टिकोणों का व्यापक विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

तालिका 2 पुरुष और महिला छात्रों के बीच उच्च शिक्षा तक पहुंच में महत्वपूर्ण अंतर

उच्च शिक्षा तक पहुंच में महत्वपूर्ण अंतर	**संख्या**	**प्रतिशत**
दृढ़तापूर्वक सहमत	145	48.33%
सहमत	85	28.33%
तटस्थ	10	3.33%
असहमत	42	14.00%
दृढ़तापूर्वक असहमत	18	6.00%
कुल	**300**	**100.0%**

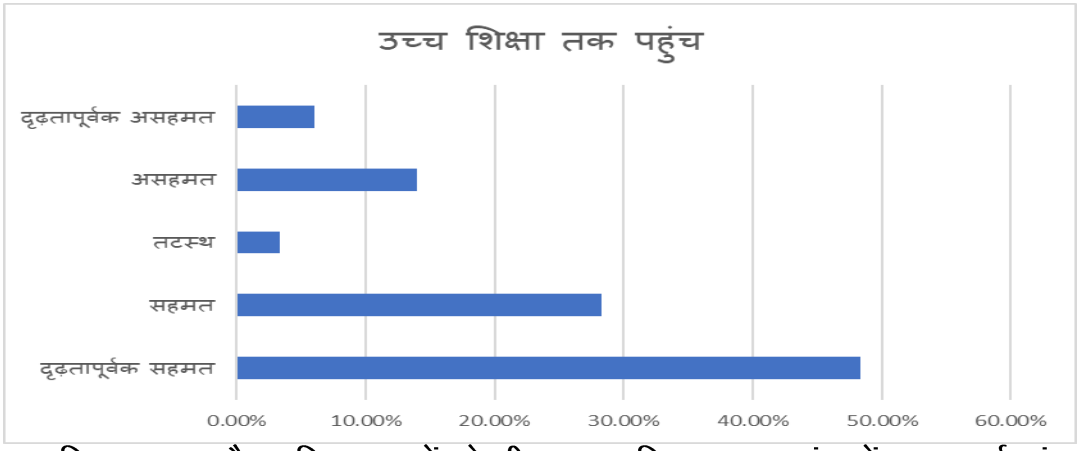

आकृति 2 पुरुष और महिला छात्रों के बीच उच्च शिक्षा तक पहुंच में महत्वपूर्ण अंतर

तालिका 2 में उत्तरदाताओं के विचार प्रस्तुत किए गए हैं कि उच्च शिक्षा में पुरुष और महिला छात्रों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएँ मौजूद हैं या नहीं। एक बहुमत, 48.33:, इस कथन से पूरी तरह सहमत है, जबकि अतिरिक्त 28.33: सहमत हैं। यह सुझाव देता है कि उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा शैक्षणिक पहुँच में लिंग विषमताओं को मानता है। इसके विपरीत, केवल 20: उत्तरदाता (संयुक्त रूप से) असहमत या पूरी तरह असहमत हैं, जो यह इंगित करता है कि उच्च शिक्षा की दिशा में महिला छात्रों को सामना करने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं के बारे में मजबूत सहमति है।

तालिका 3 वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करती हैं

वित्तीय बाधाए	संख्या	प्रतिशत
बहुत अधिक प्रभाव	120	40.00%
उच्च प्रभाव	55	18.33%
मध्यम प्रभाव	30	10.00%
कम प्रभाव	75	25.00%
कोई प्रभाव नहीं	20	6.67%
कुल	**300**	**100.0%**

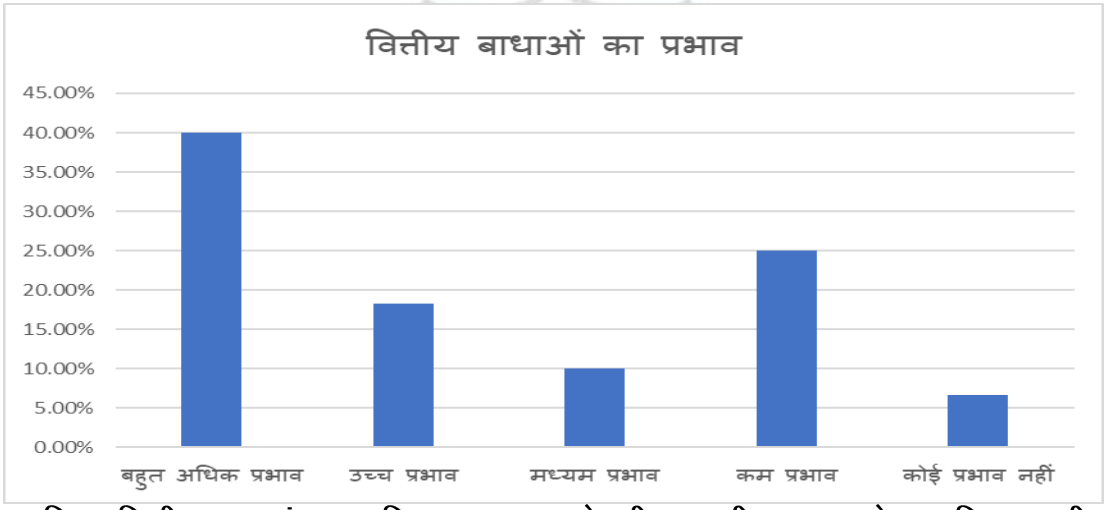

आकृति 3 वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करती हैं

तालिका 3 में दिए गए आंकड़े उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं के प्रभाव को उजागर करते हैं। एक महत्वपूर्ण 40: उत्तरदाताओं ने बताया कि वित्तीय बाधाओं का ष्बहुत उच्च प्रभावष है, जबकि 18.33: ने ष्उच्च प्रभावष का संकेत दिया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि वित्तीय मुद्दे उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख बाधा हैं, विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए। इसके अतिरिक्त, 25: ने ष्कम प्रभावष का उल्लेख किया, जबकि केवल 6.67: ने कहा कि ष्कोई प्रभाव नहीं है,ष जिससे यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय सहायता तंत्र में सुधार की आवश्यकता है।

तालिका 4 शैक्षणिक संस्थान पर्याप्त सहायता प्रदान करता है

शैक्षणिक संस्थान	संख्या	प्रतिशत
दृढ़तापूर्वक सहमत	88	29.33%
सहमत	32	10.67%
तटस्थ	100	33.33%

असहमत	49	16.33%
दृढ़तापूर्वक असहमत	31	10.33%
कुल	**300**	**100.0%**

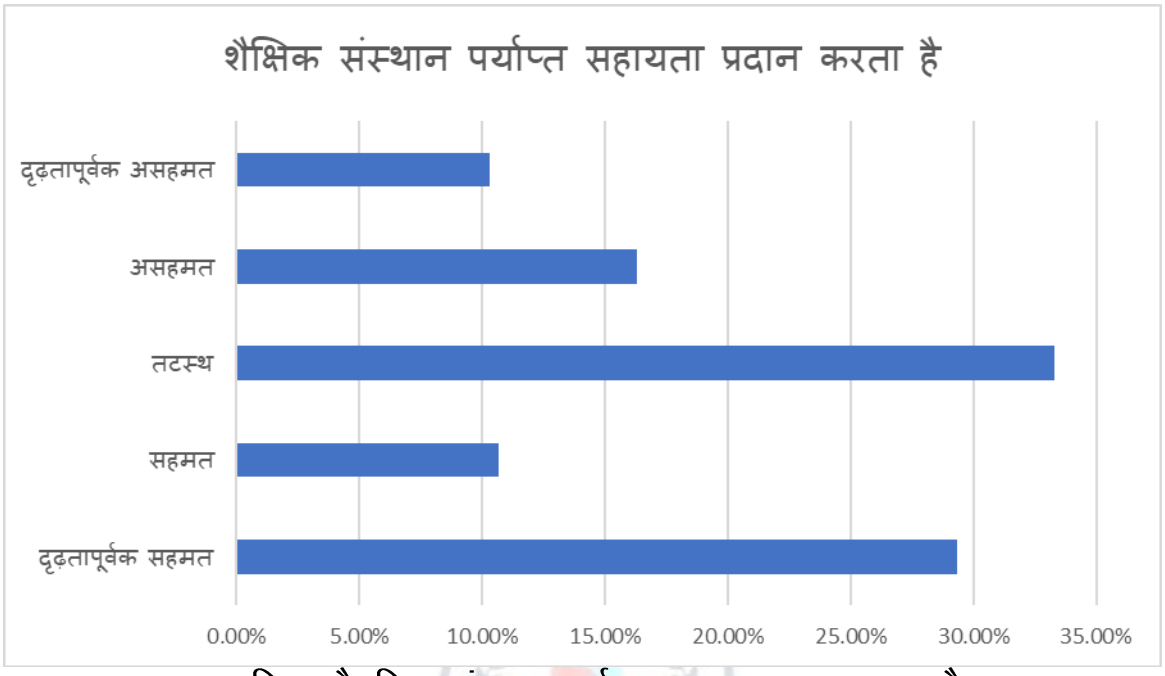

आकृति 4 शैक्षणिक संस्थान पर्याप्त सहायता प्रदान करता है।

तालिका 4 में शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की पर्याप्तता के संबंध में धारणाओं की जांच की गई है। परिणामों से पता चलता है कि केवल 29.33ः उत्तरदाता मजबूत सहमति व्यक्त करते हैं कि संस्थान पर्याप्त समर्थन प्रदान करते हैं, जबकि 10.67ः सहमत हैं। इसके विपरीत, 33.33ः उत्तरदाता तटस्थ बने रहते हैं, और 26.66ः (संयुक्त) असहमत या पूरी तरह असहमत हैं। यह छात्रों के बीच समर्थन प्रणालियों के प्रति विश्वास की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है, यह सुझाव देते हुए कि संस्थानों को छात्रों, विशेष रूप से महिला छात्रों, की बेहतर सहायता के लिए अपनी सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है।

तालिका 5 नीतियाँ उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने में सबसे अधिक प्रभावी रूप से सहायक हैं।

नीतियाँ उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतर	**संख्या**	**प्रतिशत**
महिला छात्राओं के लिए अधिक छात्रवृत्तियाँ और वित्तीय सहायता	120	40.00%
लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर जागरूकता अभियान	25	8.33%
शैक्षणिक संस्थानों में लिंग–संवेदनशील बुनियादी ढाँचा	100	33.33%
पुरुष और महिला छात्रों के समान नामांकन के लिए सरकारी आदेश	15	5.00%
अन्य	40	13.33%
कुल	**300**	**100.0%**

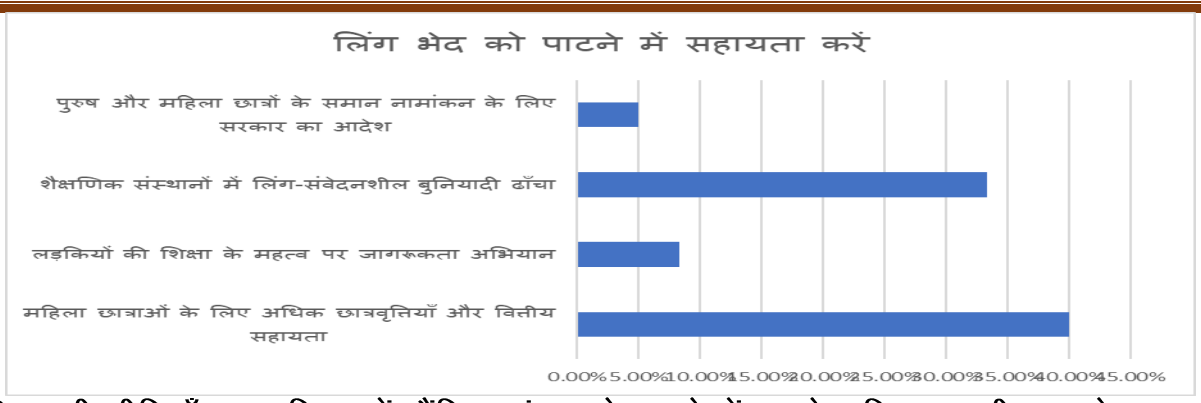

आकृति 5 की नीतियाँ उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने में सबसे अधिक प्रभावी रूप से सहायक हैं।

अंतिम तालिका उन नीतियों की पहचान करती है जिन्हें उत्तरदाता मानते हैं कि वे उच्च शिक्षा में लिंग अंतर को पाटने में सबसे प्रभावी होंगी। उल्लेखनीय है कि 40ः उत्तरदाता ष्महिला छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायताष् का समर्थन करते हैं, जो वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, 33.33ः ष्शैक्षिक संस्थानों में लिंग–संवेदनशील अवसंरचनाष् का समर्थन करते हैं, जबकि केवल 8.33ः लड़कियों की शिक्षा के बारे में जागरूकता अभियानों के महत्व पर जोर देते हैं। सरकारी समान नामांकन के लिए नियमों का समर्थन करने वाले कम प्रतिशत (5ः) यह दर्शाता है कि नियामक उपायों के समाधान के रूप में विश्वास की कमी है। कुल मिलाकर, ये परिणाम उस तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि विशेष नीतियों की आवश्यकता है जो सीधे महिला छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं का समाधान करें।

इस अध्ययन के निष्कर्ष झारखंड के रांची जिले में उच्च शिक्षा में लिंग अंतर के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ उजागर करते हैं। उत्तरदाताओं में समान लिंग प्रतिनिधित्व दोनों पुरुष और महिला दृष्टिकोणों की गहराई से जांच की अनुमति देता है। महिला छात्रों द्वारा सामना किए गए महत्वपूर्ण बाधाओं के अस्तित्व पर भारी सहमति विशेष रूप से लक्षित हस्तक्षेप की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर करती है। वित्तीय बाधाएँ एक प्रमुख रुकावट के रूप में उभरती हैं, जो महिला छात्रों के लिए वित्तीय सहायता और सहायता को बढ़ाने वाली नीतियों की आवश्यकता को बल देती हैं। इसके अलावा, संस्थागत समर्थन की पर्याप्तता के संबंध में चिंताएँ यह इंगित करती हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए ताकि सभी छात्रों की बेहतर सेवा की जा सके। अंततः, डेटा विशेष नीति उपायों की ओर इशारा करता है जो इन विषमताओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं, जिसमें छात्रवृत्तियों और लिंग–संवेदनशील अवसंरचना में वृद्धि की स्पष्ट मांग शामिल है। सामूहिक रूप से, ये अंतर्दृष्टियाँ सभी लिंगों के लिए उच्च शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए हितधारकों के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

यह अध्ययन झारखंड के रांची जिले में उच्च शिक्षा में लिंग विषमताओं पर प्रकाश डालता है, जो महिला छात्रों द्वारा पुरुष समकक्षों की तुलना में सामना की गई महत्वपूर्ण बाधाओं को उजागर करता है। 300 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण के माध्यम से, यह शोध दिखाता है कि सामाजिक–आर्थिक प्रतिबंध, सांस्कृतिक अपेक्षाएँ, और संस्थागत कमी महिला छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्षों से पता चलता है कि वित्तीय बाधाएँ कई महिला उत्तरदाताओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण संख्या आर्थिक कठिनाइयों को उच्च शिक्षा का अनुसरण न करने का प्राथमिक कारण बताती है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक कारक, जैसे कि जल्दी विवाह और घरेलू जिम्मेदारियाँ, इन चुनौतियों को और बढ़ाते हैं, जिससे महिलाओं के बीच नामांकन दर में कमी आती है। अध्ययन ने संस्थागत समर्थन में कमी को भी पहचाना है, जैसे कि लिंग–संवेदनशील अवसंरचना का अभाव और विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए सीमित छात्रवृत्ति के अवसर।

इन विषमताओं को दूर करने के लिए, अध्ययन लक्षित नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देता है। सिफारिशों में महिला छात्रों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना, लड़कियों की शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियानों को लागू करना, और संस्थागत समर्थन तंत्र को सुदृढ़ करना शामिल है। महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुँच को प्रोत्साहित और सुगम बनाने वाले वातावरण को बढ़ावा देकर, हितधारक लिंग अंतर को समाप्त करने और रांची जिले में एक अधिक समान शैक्षणिक परिदृश्य को बढ़ावा देने में योगदान कर सकते हैं।

संदर्भ

- ऐकमैन, एस., और अन्टरहेल्टर, ई. (2005)। पहुँच से परेरू शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए नीति और व्यवहार को बदलना। ऑक्सफोर्ड रिव्यू ऑफ एजुकेशन, 31(2), 251–267।

- भारत धीमान (2023) 2023 में नई मीडिया तकनीक में प्रमुख मुद्दे और नई चुनौतियाँरू एक महत्वपूर्ण समीक्षा। जर्नल ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट। एसआरसीध्जेएमएम–184।
- चेन, डब्ल्यू., और याप, एम. टी. (2019)। विकासशील देशों में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनानारू एक व्यवस्थित समीक्षा। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 31(7), 558–583।
- धीमान बी (2022) पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण और बहाली की आवश्यकतारू पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लेंस के माध्यम से। पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन 6रू 304.
- धीमान बी (2023) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा का एक महत्वपूर्ण विश्लेषणरू एक व्यवस्थित समीक्षा। ग्लोबल मीडिया जर्नल, 21रू62. धीमान बी (2023) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारतीय क्षेत्रीय सामग्री की विविधतारू एक महत्वपूर्ण समीक्षा। जे सिविल लीगल साइंस 12रू 385.
- धीमान बी (2023) सोशल मीडिया में नैतिक मुद्दे और चुनौतियाँरू एक वर्तमान परिदृश्य। ग्लोबल मीडिया जर्नल, 21रू62.
- धीमान बी (2023) सामाजिक परिवर्तन संचार के लिए उपकरण के रूप में खेलरू एक महत्वपूर्ण समीक्षा। ग्लोबल मीडिया जर्नल, 21रू61.
- धीमान, बी. (2019)। एंड्रॉइड के लिए ऑनलाइन समाचार अनुप्रयोगों के प्रभाव–एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। यूरोपियन जर्नल ऑफ बिजनेस एंड सोशल साइंसेज, 7(2), 815–819.
- धीमान, बी. (2021)। मीडिया शिक्षा और मीडिया अनुसंधान का अभ्यासरू पाँच एशियाई देशों पर एक समीक्षा। ग्लोबल मीडिया जर्नल, 19(44), 1–7।
- धीमान, बी. (2023)। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारों की मदद करता हैरू वरदान या अभिशाप?
- धीमान, बी. (2023)। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर मीडिया कवरेज का विकासरू समावेशिता की ओर एक कदम। विविध।
- धीमान, बी. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारों की मदद करता हैरू वरदान या अभिशाप? प्रीप्रिंट्स 2023, 2023030428 https://doi-org/10-20944/preprints202303-0428-v1-
- धीमान, बी. राष्ट्र निर्माण के लिए मास मीडिया में सकारात्मकता बढ़ानारू एक महत्वपूर्ण समीक्षा। प्रीप्रिंट्स.ऑर्ग 2023, 2023061320. https://doi-org/10-20944/preprints202306-1320-v1
- धीमान, डी. (2021)। छात्रों के बीच डव्ब्े के बारे में जागरूकतारू कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का एक अध्ययन। अंतःविषय संगठनात्मक अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।
- धीमान, डी. (2021)। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शोध विद्वानों द्वारा ई–संसाधनों का उपयोगरू एक केस स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी ऑर्गनाइजेशनल स्टडीज का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल।
- धीमान, डी. (2022)। मॉडल जेल, चंडीगढ़ में महिला कैदियों की स्थितिरू एक संचार अध्ययन। मॉडल जेल, चंडीगढ़ में महिला कैदियों की स्थितिरू एक संचार अध्ययन (26 अगस्त, 2022)।
- धीमान, डी. बी. (2023)। राष्ट्र निर्माण के लिए मास मीडिया में सकारात्मकता बढ़ानारू एक महत्वपूर्ण समीक्षा। 4480810 पर उपलब्ध है।
- सिंह, ए. (2020)। झारखंड में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति।ैत्छ 3686884 पर उपलब्ध है।
- नायक, के. वी., और आलम, एस. (2022)। डिजिटल डिवाइड, लिंग और शिक्षारू कोविड–19 के दौरान ग्रामीण झारखंड में आदिवासी युवाओं के लिए चुनौतियाँ। निर्णय, 49(2), 223–237.
- स्नेही, नीरू. ''भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आईसीटः अवसर और चुनौतियाँ.'' इंडियन जर्नल्स (2009)रू 231–244.